

ISHRI Bhanu Pratap Singh.]

Every effort is being made to alleviate the sufferings of the people of Andhra Pradesh 3 P.M.

SHRI N. G. RANGA (Andhra Pradesh): Sir, may I make one small suggestion that one of the Ministers from the Centre, preferably my hon. friend, Mr. Bhanu Pratap Singh, may be good enough to go there expeditiously by a plane and then go over the affected area by a helicopter and in that way gain a firsthand impression and knowledge of not only the extent of the damage but also the nature of the damage so that it would be easier for him to understand whatever report that would be coming from the State Government and then give all the possible assistance to the local Government? I may also inform my hon. friend that six of us, Members of Parliament from both the Houses, propose to go down there during the coming week-end on Friday, Saturday and Sunday and try to reach as many places as possible and come back and also submit our own report to the Union Government.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: Sir, I have myself thought to go there but day after tomorrow, I have to give replies on behalf of the Agriculture Ministry. That is what is detaining me. As soon as I am free from this duty, I propose to go to Andhra Pradesh.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, सदन में यह भी रिपोर्ट आनी चाहिए कि पहले से सूचना होते हुए भी . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): We are not discussing the statement.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही : डिस्कशन नहीं श्रीमन्, यह रिपोर्ट आनी चाहिए कि पहले से सूचना होते हुए भी एक हजार आदमी मारे गये, तो इसके लिये एडिक्वेट प्रीकाशन लिये गये या नहीं लिये गये ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. M. TRIVEDI): That is already there in the statement.

#### MOTION RE FIFTEENTH AND SIXTEENTH REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES IN INDIA—Contd.

श्री योगन्द्र शर्मा (बिहार) : उपसभा-ध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही निराशा और चिन्ता की बात है कि भाषायी अल्पसंख्यकों की 1972-73, 1973-74 की रिपोर्टों पर हम 1977 के आखिर में विचार कर रहे हैं। यदि पार्लियामेंट भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करने का मौका नहीं पायेगी तो फिर इस बात की गारंटी नहीं हो सकती है कि भाषायी अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा होगी। इसलिए सब से पहले मेरा जो निवेदन है वह यह है कि संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं कि पार्लियामेंट साल में करीब 150 दिन बैठती है और 150 दिनों में कम से कम एक दिन भाषायी अल्पसंख्यकों के समस्याओं पर, उनकी रिपोर्ट पर विचार करें। तब जबकि हमारे देश में भाषायी अल्पसंख्यक सिर्फ उर्दू की भाषा के लोग नहीं हैं। जब से भाषावार राज्यों की स्थापना हुई है, पुनर्गठन हुआ है तब से हम समझते हैं कि तमाम राज्यों को मिला कर 10-12 करोड़ लोग भाषायी अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं। उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो हमारे संविधान में उनको संरक्षण दिये गये हैं, उनके ऊपर विचार करना पार्लियामेंट का एक बहुत ही अहम कर्तव्य है। इसलिए हमारा पहला अनुरोध यह है कि इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि हर साल कम से कम एक दिन तो हमें अवश्य निकालना चाहिए ताकि हम भाषायी अल्पसंख्यकों की रिपोर्ट पर विचार कर सकें। जहां तक रिपोर्टों का सवाल है रिपोर्ट पढ़ने के बाद दिल फट जाता है। दोनों रिपोर्टों से मालूम होता है कि हमारे

संविधान में भाषायी अल्पसंख्यकों को जो भी अधिकार दिए गए हैं और संविधान में ही नहीं बल्कि देश के तमाम मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था कि भाषायी अल्पसंख्यकों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको कैसे लागू किया जाये उसके सिलसिले में जो कुछ सर्व-सम्मत कार्यक्रम तैयार किया गया, तमाम की अवहेलना हो रही है। यह दोनों रिपोर्टें भाषायी अल्प-संख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा और अवहेलना की रिपोर्टें हैं। हालत यहां तक पहुंची है कि बेचारा कमिश्नर लिखता है, वह स्टेट गवर्नमेंट से पूछता है तो वे परवाह नहीं करतीं। राज्य सरकारें परवाह नहीं करती हैं। उनके सवालों का जवाब नहीं देती हैं। आंकड़े मांगते हैं तो आंकड़े नहीं मिलते हैं। यह तो बेचारा एक असहाय मालूम होता है। उसके साथ रोने की तबियत करती है। जितना भी चाहे प्राइमरी एजुकेशन का सवाल हो, सैंकेंडरी एजुकेशन का सवाल हो, अपनी जवान में दरदवास्त देने के अधिकार का सवाल हो, इनके मुताबिक जो रिपोर्टें हैं वह बहुत ही निराशाजनक हैं और मंडल जी को खुशी होगी यह तो कांग्रेसी शासन के समय की है इसलिए हमें कोई विषेध चिन्ता नहीं। लेकिन यह कांग्रेसी शासन या जनता पार्टी के शासन का सवाल नहीं है और हम समझते हैं कि इसको पार्टी का सवाल बनाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वही सवाल अब भी जारी है बल्कि हम तो यह कहेंगे अब उस सिलसिले में और भी तेजी की जा रही है इसलिए इसको पार्टी के झगड़े का सवाल न बना कर देखें। जिन चीजों को हमने संविधान में स्थान दिया है और बहुत ही समझ-बूझ कर दिया है उनकी रक्षा करना हम सब का कर्तव्य है और अभी हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम उन छटनाओं और उदाहरणों में नहीं जाना चाहेंगे जो इन दोनों रिपोर्टों में भरे पड़े हैं। हम कुछ हाल की बातों को लेंगे। हम जिस प्रदेश से आते हैं मंडल जी भी उसी प्रदेश से आते हैं। अभी, मान्यवर,

त्रिभाषी फार्मूला जो स्वीकृत किया गया था जब से बिहार में नयी सरकार आयी है तब से उस त्रिभाषी फार्मूले से उर्दू को निकाल दिया गया है। कम से कम बिहार, उत्तर प्रदेश जहां पर कि उर्दू भाषा भाषियों की बहुत बड़ी संख्या है...

**श्री सिकन्दर बली वज्र (महाराष्ट्र) :**

80 लाख।

**श्री योगेन्द्र शर्मा :** हम यदि नेशनल इन्टिग्रेशन चाहें, राष्ट्रीय एकीकरण चाहें और हमारा संविधान चाहता है तो कम से कम हम उर्दू को त्रिभाषी फार्मूले के भीतर तो रखें। इन दोनों राज्यों में जहां उर्दू रखी भी गयी थी फिर निकाल दी गयी। क्यों निकाल दी गयी? कोई खुलासा नहीं है। हमारे बिहार में ओमन-6 ट्रेनिंग कालेज है और 90 ट्रेनिंग स्कूल हैं। 6 ट्रेनिंग कालेज शिक्षकों को शिक्षित करने के लिए और 90 ट्रेनिंग स्कूल हैं। लेकिन उनमें कितने उर्दू शिक्षकों को ट्रेड करने की गुंजाइश है? सुनकर हमको शर्म आती है क्योंकि हम भी बिहार प्रदेश से आते हैं, सिर्फ एक। और जब यह सवाल उठाया जाता है कि क्यों नहीं उर्दू शिक्षक रखे जाते हैं तो कहा जाता है कि उर्दू शिक्षक नहीं मिलते हैं। 90 ट्रेनिंग स्कूल और 6 ट्रेनिंग कालेज हैं और उर्दू भाषी केवल एक तो कहां से आपको ट्रेड शिक्षक मिलेंगे। उत्तर प्रदेश को ले लें। उत्तर प्रदेश में जब बहुगुणा मंत्रिमंडल था, बहुगुणा जी आपकी सरकार के भी मंत्री है, उन्होंने 4 हजार शिक्षकों को बहाल किया था, नियुक्त किया था।

**श्री विश्वम्भर नाथ पांडे (नाम-निर्दिष्ट) :**

कमलापति जी ने मुकर्रर किया था और बहुगुणा जी ने काम आगे बढ़ाया था।

**श्री योगेन्द्र शर्मा :** कुछ भी कह लें। हमारी शिकायत यह है कि आज तक उनको परमानेंट नहीं किया गया और अब खतरा इस बात का आ गया है कि उनमें से एक हजार शिक्षक छांट दिये जायेंगे इस नाम पर कि

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी है जबकि ट्रेनिंग देने के लिए कोई कोशिश नहीं की गयी है। दिल्ली को ले लें। दिल्ली में उर्दू भाषी विद्यार्थी जो उर्दू के माध्यम से पढ़ते हैं उनको उर्दू में प्रश्नपत्र नहीं दिये गये बल्कि उनको हिन्दी में प्रश्नपत्र दिये गये। मैं हिन्दी भाषी हूँ और हिन्दी भाषी होने का मुझे फायदा है और वह भी इस बात के लिए संघर्ष कर रहा हूँ अपनी सीमा के भीतर कि वह दिन आये जब हिन्दी देश की सम्पर्क भाषा हो राज भाषा हो। लेकिन यह भी वर्दाश्वत नहीं किया जा सकता है यह तो हमारे संविधान की भारतीय जनतंत्र की पूरी स्पिरिट के खिलाफ है कि उर्दू भाषी विद्यार्थी उर्दू के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं लेकिन प्रश्नपत्र हम उन्हें दूसरी भाषा में दें। यह तो संवैधानिक अधिकारों पर हमला है और उस संवैधानिक अधिकार पर हमला हो रहा है। श्रीमन् अभी-अभी दिल्ली प्रशासन ने करीब 400 हेडमास्टरों का तबादला किया है। तबादले होते हैं होने चाहिए। लेकिन वह खास मकसद से होते हैं। और यह तबादले इस तरह से किये गये कि 30 उर्दू स्कूल के जो उर्दू-भाषी हेडमास्टर थे उन्हीं बच्चों को मुक्ति मिल गई—उनको अलग कर दिया। यह हो रहा है और हम सुरक्षण की बात करते हैं। इसी तरह से राजस्थान को लें। राजस्थान में पहले उर्दू अकादमी के लिए 2 लाख रु० की ग्रांट थी उसको घटा कर 30,000 रु० कर दिया। हजारों उदाहरण हैं जो पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि भाषायी अल्पसंख्यकों के वे अधिकार जिनको हमने संविधान में सुरक्षित किया है उनकी हत्याएं हो रही हैं। ये हत्याएं क्यों हो रही हैं। हम सिर्फ जनता पार्टी की सरकार पर दोष नहीं देना चाहते हम देश की एक मनोवृत्ति पर दोष देना चाहते हैं और वह मनोवृत्ति आज बहुत जोरों से उभर रही है और वह मनोवृत्ति कांग्रेसी शासन जब था—कांग्रेस के लोगों का जब शासन था—उस वक्त भी वह मनोवृत्ति थी।

और वह मनोवृत्ति क्या है? हमारे पूर्ववक्ता ने बिल्डज में गृह मंत्री की मुलाकात का एक हवाला दिया। 12 नवम्बर का बिल्डज है उसमें गृह मंत्री के साथ बिल्डज के संपादक कराँजिया की भेंट के दौरान सवाल और जवाब की रिपोर्ट छपी है। इसमें किसी बात का खंडन नहीं किया गया है, कांटेडिक्शन नहीं किया गया है। और कहा क्या गया है—जब उनसे यह पूछा गया कि जनता पार्टी के घोषणापत्र में यह कहा गया है कि उर्दू को उचित स्थान दिया जाएगा, इयू एलेस दिया जाएगा तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर में बहुत सी बातें कहने के बाद उन्होंने कहा कि साहब उर्दू जो है वह तुर्कियों की और मुगलों की भाषा है—उर्दू वाज इंपोज्ड बाई द टवर्स आर द मगोन्स हू केम फ्राम आउटसाइड। उर्दू जो पैदा हुई भारत की भूमि में, भारत की धरती में उस उर्दू को कहा जाता है कि वह तुर्कियों की भाषा थी, मुगलों की भाषा थी। हम समझते हैं यह बात वही कह सकता है जिसने शायद अपनी सारी जिदगी में कभी यह नहीं कहा होगा: इंकिलाब जिदाबाद। यह इंकिलाब जिदाबाद उर्दू ने हम को दिया है। ऐसी बात वही कह सकता है जिसने अपनी सारी जिदगी में कभी यह नहीं कहा होगा, कभी यह नहीं गाया होगा—सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा। और उस भाषा को आप तुर्कियों की भाषा और मुगलों की भाषा कहते हो। तो यह जो मनोवृत्ति है यह मनोवृत्ति जब तक रहेगी तब तक इस देश में भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस मनोवृत्ति के खिलाफ हम लड़ें। हमें खुशी होती है कि मंडल जी कहते हैं हम गांधी जी के विचारों पर चलने वाले हैं। गांधी जी का क्या विचार था? गांधी जी तो हिन्दी और उर्दू दोनों को मिला कर एक हिन्दुस्तानी भाषा बनाना चाहते थे इस बात की जिदगी भर कोशिश करते रहे। क्या उन्होंने कहा था कि उर्दू

तुर्कियों की मुगलों की भाषा है ? आज आप गांधी जी की शपथ लिने वाले लोग कहते हैं कि उर्दू तुर्कियों और मुसलों की भाषा है ।

इतना ही नहीं है श्रीमन् उसी बयान में कहा गया—उर्दू कैन्नोट बी इम्पोज्ड आन द हिन्दूज। सवाल कहां उठता है ? कौन कहता है कि उर्दू को हिन्दुओं पर इम्पोज करो ? उर्दू के इम्पोजिशन का सवाल कहां उठता है ? सवाल तो यह है कि जो उर्दू भाषाभाषी हैं, अर्थात् जिनकी मातृभाषा उर्दू है, उनको जो अधिकार संविधान में हैं और हमारे विचार से वे अधिकार काफी नहीं हैं; और भी अधिकार मिलने चाहिए । उन अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए । और जब समस्या यह है तो कहा जाता है कि इम्पोज नहीं किया जा सकता है । लादा नहीं जा सकता है क्योंकि बहुमत इसके खिलाफ है । तो क्या बहुमत के आधार पर हम यह तय करेंगे ? संविधान की धारा 29 में यह कहा गया है कि इस देश के लोगों की, हर समुदाय की भाषा और संस्कृति की रक्षा होगी । यह हमारा संविधान है । इसकी क्या हम बहुमत और अल्पमत की ताकत के आधार पर तय करेंगे और यदि हम ऐसा करेंगे तो जाहिर बात है कि तमाम भाषायी अल्पसंख्यकों के अधिकार खत्म हो जायेंगे और यदि ऐसा हुआ तो फिर हम को वहीं जाना पड़ेगा जहां कि पाकिस्तान पहुंच गया है—एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य । तो हम समझते हैं कि यह जो मनोवृत्ति है, जिसके कारण अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है उसके खिलाफ लड़ना होगा । उसको खत्म करना होगा और जब तक यह नहीं होगा तब तक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकेगी ।

इस सिलसिले में यह सवाल उठता है कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की या दूसरे प्रदेशों की सेकिड लैंग्वेज बनाया जाय । अब सेकिड लैंग्वेज का सवाल बहुत टेढ़ा है और इसमें हम

पड़ना नहीं चाहते कि वह सेकिड लैंग्वेज हो या थर्ड हो या फोर्थ हो । सवाल है उनके अधिकारों का । उनको अपनी भाषा में पढ़ने का अधिकार होना चाहिए प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक । अपनी भाषा में उनको सरकारी दफ्तरों में, कार्यालयों में और कोर्ट्स में दरखास्त देने का अधिकार होना चाहिए और उनको अपनी ही भाषा में उसका जवाब पाने का अधिकार होना चाहिए और इस तरह के जो उनके अधिकार हैं हम समझते हैं कि कमोवेश उन पर अमल होना ही चाहिए । बिहार से कभी दस लाख दस्तखत ले कर, कभी उत्तर प्रदेश से 20 लाख दस्तखत ले कर लोग राष्ट्रपति जी के पास आये थे । उनकी जो मांगें थीं उनकी गारंटी होनी चाहिए और इस झगड़े में हम को नहीं पड़ना चाहिए कि वह प्रदेश की सेकिड लैंग्वेज हो या थर्ड लैंग्वेज हो या फोर्थ लैंग्वेज हो । तो उनके अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए यह मुख्य प्रश्न है और हमारे संविधान में इस बात की व्यवस्था है और धारा 347 में इसी लिये कहा गया है कि यदि देश के किसी भाग का एक समुदाय अपनी भाषा के संबंध में सरकारी काम काज के सिलसिले में कोई मांग करे तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उसके लिये उचित आदेश दें । हम मांग करते हैं कि यह सरकार राष्ट्रपति जी के पास ऐसी अनुशंसा भेजे कि बिहार और उत्तर प्रदेश और वे प्रदेश जहां कि उर्दू भाषा-भाषी लोग हैं, कम से कम दस फीसदी जहां भी हैं, वहां पर उनके अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए और इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि वह दूसरी भाषा हो या तीसरी भाषा हो और राष्ट्रपति जी को इसके लिये उचित आदेश देने चाहिए ।

अंत में, श्रीमन्, मैं बिहार से आता हूं । हम समझते हैं कि उर्दू भाषा बोलने वालों के बाद हमारे देश में भाषायी अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ी संख्या आदिवासियों की है और बिहार में तो है ही और इसको ले कर वहां एक अलग प्रान्त बनाने का आंदोलन उठा

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

हुआ है। फिर हम कांग्रेस और जनता पार्टी का सवाल इस में नहीं उठाना चाहते क्योंकि उस आंदोलन में जनता पार्टी के लोग भी हैं और कांग्रेस के लोग भी हैं, यहां तक कि जनता सरकार के एक मंत्री भी हैं जो आंदोलन को चला रहे हैं कि छोटा नागपुर और संथाल परगना को एक अलग प्रान्त बनाया जाय। यदि वहां आदिवासियों की बहुलता होती, यदि वह 51 या 50.5 प्रतिशत भी होते तो हम इसका समर्थन करते कि वहां एक आदिवासी राज्य बनना चाहिए। लेकिन छोटा नागपुर और संथाल परगना दोनों को मिला कर हम देखते हैं कि आदिवासियों की संख्या वहां कुल 30 फीसदी है। तो कैसे वह अलग प्रान्त बन सकता है और अलग प्रान्त बनेगा तो उसकी भाषा क्या होगी? उस प्रान्त की आफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? तो पूरे बिहार को इस भाषा के दलबदल में खत्म करने की एक योजना है। इस मायने में हम प्रधान मंत्री श्री मोरारजी को बधाई देना चाहते हैं कि वह रांची गये थे वहां उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे बंटवारा नहीं चाहते। लेकिन साथ ही साथ श्रीमन् वहां हमारे आदिवासी आप जानते हैं, सबसे ज्यादा शोषित हैं, पीड़ित हैं। उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। हम चाहते हैं कि पूरे क्षेत्र में कम से कम दो ऐसे इलाके हैं जहां पर कि आदिवासियों की संख्या 50 फीसदी से अधिक है, 60 फीसदी करीब है। तो इन दो क्षेत्रों में आदिवासी स्वशासी प्रशासन की स्थापना हो। उनके क्या क्या अधिकार हों, इसके लिए हमें प्रतिनिधि सभा बुलाकर, सम्मेलन बुला करके विचार करना चाहिए। लेकिन उनको यह स्वशासी अधिकार बिहार के अन्दर इन दो क्षेत्रों में मिल सकते हैं। ( *Time Bell Rings* )

श्रीमन्, आपने घंटी बजाई है, इसलिए उनका नाम नहीं लेता। आखीर में मैं एक बात कह कर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा

और वह यह कि भाषायी अल्पसंख्यक कमिशनर जो बेंचारा है उसकी कोई सुनता ही नहीं। अभी अभी मंडल जी ने कहा कि जो नया कमिशनर गया वह पूरा पद या समय का नहीं है, वह कुछ और भी काम करता है। इसका मतलब है कि और भी कुछ वह कर सकता है। इसलिए मेरी मांग यह है कि यदि आप भाषायी अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं तो इस कमिशनर की शक्ति को बढ़ाइए, उसका ज्यादा सक्षम कीजिए, उसको ज्यादा सशक्त कीजिए। हम चाहेंगे कि हर एक राज्य में इस तरह की चीज होनी चाहिए। हर जिले में भाषायी अल्पसंख्यक अधिकार खास तौर पर उनको दिये जायें। हमारी अरील है कि हमारे इन मुद्दों के अनुसार आप अमल करें। हम आशा करते हैं कि मंडल जी उस गलत मनोवृत्ति के खिलाफ संघर्ष करेंगे जिसके कारण भाषायी अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है।

SHRI NRIPATI RANJAN CHOU-DHURY (Assam): Sir, Prof. Ramlal Parikh, while making his observations, suggested that the Report of the Commissioner for Linguistic Minorities should be placed in time and discussed in the House immediately after it is submitted to the Government. But better late than never. Even then, when we are discussing the Reports after three or four years, the situation has not changed. The recommendations which were made in these Reports still remain unimplemented. In view of this, I think it would be good to discuss these Reports in the House even now. Moreover, with this new Government coming here at the Centre, a new situation has been created in the country so far as the linguistic and religious questions are concerned. This new situation has developed because of the views expressed in the statements of the members of the present Government regarding language. We are concerned with the linguistic minorities only. The over-enthusiasm being

shown by responsible members of the Union Government regarding the use of Hindi in all official matters has created tension in the non-Hindi speaking areas of the country, particularly in the South, and every day articles and letters and appearing in the Press in which a popular agitation is being carried on against imposition of Hindi. Secondly, Sir, the Education Minister, Dr. Chunder, announced on the floor of the House that he is not going to accept education as a Concurrent subject in view of his non-acceptance of the 42nd Amendment to the Constitution. Sir, this inclusion of education in the Concurrent List has always been very much welcomed by the linguistic minorities all over the country. But the Minister, only the other day in this House, said that he was not going to accept this position. This has created an apprehension in the minds of the linguistic minorities all over the country that this Government may not deliver the goods so far as the implementation of the report of the Linguistic Minorities Commission is concerned.

Again, we have seen the Press report about Shri Jayaprakash Narayan's prescription of smaller States and also the reported proposal of the Home Ministry for the reorganisation of States. Sir, this sort of reports and statements by responsible persons in the Government and also the conscience-keeper of the Janata Party Government have only encouraged forces of disintegration in this country. Sir, these three points which I mentioned have created a new situation. Therefore, when we are discussing the Fifteenth and the Sixteenth Reports of the Commissioner of Linguistic Minorities, naturally, we have to be cautious while making our observation.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA) in the Chair]

Also this discussion will give the Government an opportunity to clarify their position on these issues.

Sir, the safeguards of linguistic minorities are mainly derived from

the Provincial Education Ministers' Conference of 1949, the Government of India Memorandum 1956, the Ministry of Home Affairs Press note dated July 14, 1958, Discussions of the Southern Zonal Council in 1960 and the statement issued by the meeting of the Chief Ministers and the Central Ministers in August, 1961. Sir, in this process of formulating a national policy regarding these safeguards to the linguistic minorities nowhere the representatives of the linguistic minorities have been taken into confidence. These issues were discussed only at the official level with the Central Ministers, the Chief Ministers, the officials and the linguistic minorities spread all over the country.

Again, the hon'ble Minister has agreed that this is a land of minorities. We are all minorities. Some who are in a majority in Bihar are in a minority in Orissa. Somebody who is in a majority in West Bengal is in a minority in Assam. So we all are minorities somewhere. The same community which is in a majority in one place is in a minority in the other parts of the country. In that sense all the linguistic groups are minorities in the some areas or in the pockets. Everybody is a minority. So, this is a land of minorities. For instance, Mr. Rajnarain who is very much a vocal person an over-enthusiastic Hindi propagator—self-styled, of course; he is not employed for that purpose—thinks that because he is from U.P. and U.P. is a predominantly Hindi-speaking State, whatever he says about Hindi should hold good everywhere. But in West Bengal the Hindi-speaking people are in minority and his own linguistic group have trouble in other States—in West Bengal, Assam and Orissa. If one is so much chauvinist, his own people will be in trouble in other places. So, Sir, my contention is that those who sit at the table for formulating the policy for linguistic minorities will not be able to solve the problem because those who sit at the table are people who are in power.

Linguistic minbri-

[Shri Nripati Ranjan Choudhury]

ties who live in pockets have their own special problems and these problems do not reach this table where these decisions are taken. As a result, in spite of all our good efforts and the safeguards we have formulated, so far we have not been able to give even proper guidelines for the implementation of the safeguards for the linguistic minorities.

Sir, take the case of the Three-language Formula for instance. In 1961, in the Chief Ministers' Conference they thought this would solve the problem but it has created problems for all the States. Shri Yogendra Sharma has mentioned about Urdu's position in Bihar and Uttar Pradesh. I will give you two other instances. One is in Delhi itself and that is about Punjabi. There is a reference to it on page 60 of the Sixteenth Report.

"Representatives of Punjabi-speakers complained that the Three-language Formula had been revised to the disadvantage of linguistic minorities who had been debarred from studying all the three languages upto class XI."

Then there is the other case which I will place before you because it has created different problems in different States. Now, in Assam, Bengali-speakers of Cachar district complained that the Government of Assam, as a matter of policy, decided to introduce Assamese as a compulsory subject in all the secondary schools in the State. Accordingly, the Board of Secondary Education, Assam, issued a circular embodying Assamese as a compulsory core subject with effect from 1973-74 academic session. The matter was taken up with the Assam Government. Then the Assam Government had, however, sought further clarification from the Ministry of Home Affairs whether the decision taken by the State Government of Assam to make Assamese a compulsory subject was within the framework of the Government of India policy on the safeguards

for linguistic minorities. Now, what is the problem? For the linguistic minorities in Assam, whose mother tongue is not Hindi, you Three-language formula virtually becomes a four language formula. Yours is a Three language Formula. There is no provision for the study of mother tongue as a subject. So a problem is created there to choose between their mother tongue and Hindi or the regional language. So it is a now situation that has to be sorted out. And what does the Commissioner say? In the 1973-74 Report, the Commissioner accepts this position.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You will have to finish now.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: Sir, I have spoken for only, five minutes. My time is fifteen' minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): It has been written here that you started at 3.23 P.M.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: It is not correct, Sir. I am' looking at the clock. I started after 3.30 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri U. K. LAKSHMANA GOWDA) It is written here.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOU-DHURY; It is not correct:

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): You take two minutes more and finish.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOUDHURY: It won't do, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): All right, another three minutes.

SHRI NRIPATI RANJAN CHOU-DHURY: No, Sir. Five to seven minutes you have to give me.

The Commissioner says: There is no denying the fact that barring the six-States where the regional language is Hindi, the three-language formula

adopted by the Chief Ministers' Conference of 1961 automatically becomes a four-language formula for any of the linguistic minorities whose mother tongue is not Hindi. This aspect of the problem deserves reexamination at the Central level. Therefore, Sir, I request the Minister to kindly re-examine this three-language formula and see what can be done in this respect to sort out different problems being faced by linguistic minorities in different ways in different States.

Then, Sir,, the function of the Commissioner has already been stated by the Minister. So, I am not elaborating these things. He has already made those points. The Commissioner's function is only to enquire, investigate, report and recommend. Mind it,, he has no mandatory power and his recommendation goes unheeded to toy State Governments. You will be surprised to know that the State Governments do not even co-operate in supplying the data or information required by the Commissioner. So, Sir, about these safeguards—when you don't give time, I am just concluding, I am not taking more time—very few of the safeguards mentioned in the National policy have been sincerely pursued by State Governments. In this regard,, generally the linguistic minorities all over the country feel that their interest will not be properly looked after if the administration of the safeguards in respect of linguistic minorities is kept as a State subject. So, I will request the Minister to consider the point whether they can take over the administration of safeguards of the linguistic minorities and make it a Concurrent subject. After passing of the 42nd Constitution Amendment 'Education' automatically comes under the Concurrent List. If they are contemplating to amend this, it is a different thing, but I would request that they should allow 'Education' to remain in the Concurrent List. They should also bring the administration of the safeguards in respect of the

linguistic minorities under the Concurrent List.

Lastly, I want to mention two more points. In order to create a congenial atmosphere for national integration it is time for the members of the Union Government not to give stress to talk on any sensitive issues like language or religion. This remark made by Choudhury Charan Singh, which has appeared in the Blitz, is really unfortunate. The way some of the members of the Union Government behave as protagonists of Hindi, has also agitated the minds of many of the non-Hindi speaking people, particularly South Indians. It is good if we create a climate of an understanding and for that the members of the Union Government should also maintain some restraint. Last of all, I would like to make one point and that is regarding the States Reorganisation Commission that has appeared in the press now-a-days. The States Reorganisation Commission,, in its report, had not done proper justice to the linguistic minorities in the country. In that report, it gave more weightage to the political and the economic considerations, and to the linguistic consideration was not very much there and the demands of the linguistic minorities in different States received less attention from the States Reorganisation Commission. And., now, as a result. Sir, this problem is everywhere in this country; and there is a cessassianist tendency in many parts. The statements made by Shri Jayprakash Narayan and also the press reports about the thinking of the Home Ministry has created a lot of confusion in the country. Of course, the Prime Minister, I think in Lucknow, yesterday, told the press to go somewhat slow in this matter. You know, Sir, what happened when the States were reorganised. Why should the question be reopened now? It seems he is not in favour of reopening the question now. Any way, he said that the reorganisation of the States can be considered later in a peaceful atmosphere. The Prime Minister in the statement expressed a lot of restraint. I believe



[Shri Nripati Ranjan Choudhury]

the other Members of the Union Cabinet will also maintain that much restraint while they show their enthusiasm for Hindi.

Sir, with these words, I again request the Minister to take the responsibility for the safeguard of linguistic minorities in the hands of the Central Government. I also pray, Sir, that education should remain in the Concurrent List, and, if they have any contemplation of taking it out of the concurrent list, I would request them not to do so.

With these words, I resume my seat. Thank you, Sir,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Shri Ananda Pathak. There are a large number of speakers. We will have to limit the time.

**श्री आनन्द पाठक (पश्चिमी बंगाल) :** मान्यवर, यह जो रिपोर्ट है, इससे पता चलता है कि संविधान में जो सुविधाएं लिग्विस्टिक माइनर्टीज के लोगों को दी गई हैं वे व्यावहारिक क्षेत्र में देखा जाए तो नहीं मिल रही हैं। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कोई संकेत नहीं है कि भविष्य में क्या किया जाएगा। यह रिपोर्ट 1974 साल के अंत तक के जून महीने की रिपोर्ट है अब तक इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन आ गया हो, ऐसा भी मालूम नहीं पड़ता। क्योंकि इस प्रकार की रिपोर्ट बार बार आती है तो भी देखा जाता है कि माइनर्टीज के लोगों को लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए कि प्राइमरी शिक्षा के बारे में, सैकंडरी शिक्षा के बारे में देखे जाते हैं कि सरकार इन लोगों को अधिक सुविधाएं अभी तक नहीं दे पा रही है। मेरा कहना यह है कि हमारे संविधान में बोला गया है कि जो लिग्विस्टिक माइनर्टीज के लोग हैं उनको कानून की दृष्टि से समान रूप से देखा जाएगा लेकिन व्यावहारिक क्षेत्र में नहीं होता है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि

हरिजनों पर, आदिवासियों पर जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। हरिजनों और आदिवासियों पर जुल्म हो रहे हैं और नाना प्रकार की असुविधाएं उन्हें हो रही हैं। इसलिए यह सब हटाने के लिए जब तक कोई ठोस प्रबन्ध नहीं होगा तब तक कितनी भी रिपोर्ट निकालें ज.ए., कोई सुधार होने वाला नहीं है। हम यह भी देखते हैं कि विभिन्न जगहों पर दंगे होते हैं। जब भी दंगे होते हैं उनको सेफगाइड नहीं मिलता है। उन लोगों में असन्तोष फैल जाता है दंगे होते हैं। उन्हें सुविधाएं प्राप्त होती हैं और हमें नहीं हो रही हैं जब तक यह फीलिंग रहेगी तब तक यह दंगे होते रहेंगे। इसलिए मेरा यह कहना है कि उनको जो विशेष सुविधाएं देने की बात कही गयी है उनको अच्छी तरह से लागू करने की दिशा में कुछ करना चाहिए। परन्तु हम देखते हैं कि हमारी जो मातृभाषा नेपाली है जिसकी मान्यता के लिए इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है उसके लिए बार बार बोला जाता है कि मान्यता नहीं दी जायगी। इसलिए ऐसा देखा जाता है कि विभिन्न जगहों पर एक असहाय अवस्था है। 'हम लोगों को कुछ भी सुविधायें नहीं मिल रही हैं' ऐसी भावना बढ़ रही है। इसलिए मेरा कहना है कि जनता पार्टी की सरकार कुछ नये दृष्टिकोण अपनाये तब जाकर आप यह आन्दोलन का कारण दूर कर सकेंगे नहीं तो जो धारा चल रही है उसी रास्ते पर यदि आप चलेंगे तो जो यह फीलिंग्स हैं वह कभी भी दूर नहीं होंगी। भाषा की वजह से हमारी बहुत सी समस्याएँ हैं। नेपालियों की संख्या भारतवर्ष में प्रायः 50 लाख है। काफी दिनों से वे अपनी भाषा के बारे में मांग कर रहे हैं। अभी अभी हमारे मंत्री महोदय बोल रहे थे कि किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची में अन्तरमुक्त करने से ही सब कुछ समस्या हल नहीं हो जायगी। परन्तु अन्तरमुक्त न होने पर भी बहुत सी सुविधाएं दी जा सकती हैं। मान्यवर, विभिन्न सर्विसेज में एप्लाइ करने के लिए आठवीं अनुसूची में वह भाषा होनी चाहिए

अभी कुछ दिन पहले इन्कम टैक्स इंस्पेक्टर के पदों के लिए एप्लाय करने के लिए यह लिखा गया था कि अप्टम अनुसूची में शामिल की हुई किसी एक विशेष भाषा में होनी चाहिए। तो इस प्रकार अगर कोई नेपाली भाषा के अलावा दूसरी भाषा नहीं जानता है तो वह उस परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाता है।

दूसरा प्रश्न यह है कि जो माध्यमिक शिक्षा में 10वीं कक्षा तक उन लोगों को आठवें शिड्यूल की कोई न कोई भाषा पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता है मान लीजिए कि उसे भाषा का ज्ञान नहीं है तब भी उसे बाध्य होकर वह भाषा पढ़नी पड़ती है। जैसे यू०पी०एस०सी० में जो इक्जामिनेशन होते हैं उसमें भी बोला जाता है कि आठवीं सूची में जो भाषायें हैं उन्हीं में से एक लेकर आप परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो इसी बात से देखा जाता है कि विभिन्न तरीकों से उन्हें वंचित किया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता देने के लिए, जिसके लिए कि इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, अब समय आ गया है और मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। कुछ दिन पहले हमारी नेपाली भाषा के लिए एक शिष्ट मंडल आया था तब हमारे माननीय प्रधान मंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई लेकिन बातचीत के बाद जो वक्तव्य निकला और उन्होंने जो पर्चा निकाला वह वर्बेटिम था, उसमें दिखायी देता है कि अभी भी वही अनुभव है जैसा पहले था। इसमें शंका प्रकट की गई कि क्या आपकी भाषा यहां की भाषा है, यह तो नेपाल की भाषा है। मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं कि यह गवर्नमेंट की धारणा क्यों है कि यह तो नेपाल की भाषा है? यह तो भारत की सब से पुरानी भाषा है इसकी उत्पत्ति संस्कृति से हुई है, प्राकृत भाषा से आई है मूलभूत रूप से यह भारत से आई हैं क्षेत्रीय भाषा से जन्मी है। लेकिन यह सब

होते हुए भी क्यों यह बोला जाता है कि यह नेपाल की भाषा है, भारत की भाषा नहीं है। यह बहुत अन्याय की बात है। यह भाषा इतनी समृद्ध भाषा है कि यह केवल हमारे दार्जिलिंग में ही नहीं बोली जाती है बल्कि सिक्किम में, आसाम में बोली जाती है और भारत के विभिन्न राज्यों और सब पहाड़ी जगहों में भी बोली जाती है। अभी अभी सिक्किम विधान सभा में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार को निवेदन किया गया है कि इस भाषा को अप्टम सूची में अंतर्भूत किया जाए और इसके आगे ही पश्चिम बंगाल सरकार में वहां की विधान सभा में एकमत होकर प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय सरकार को निवेदन किया गया है कि इस भाषा को संविधान की अप्टम सूची में अंतर्भूत किया जाए। इसलिए महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि नेपाल भाषा-भाषी लोग, जो 50 लाख से ज्यादा यहां हैं, बहुत असन्तुष्ट हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं यह भाषा इतनी समृद्ध है कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, नेपाल है, भूटान है, दूसरी जगहें हैं जहां नेपाली भाषा का प्रचलन है। इस रिपोर्ट में जब मैंने पढ़ कर देखा तो रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि विभिन्न जगहों में सरकारी रूप से यह माना गया है कि आसाम में इसका अस्तित्व है, मेघालय में है, सिक्किम में है, पश्चिम बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में है। तो यह सब होते हुए भी, इसके समृद्ध होते हुए भी इसको अप्टम सूची में अंतर्भूत करने के बारे में अस्वीकार किया जाता है।

आखरी बात मुझे यह कहनी है कि जो हमारे संविधान की 351 धारा है उसमें कहा जाता है कि हिन्दी को समृद्ध करने के लिए यह अनुसूची रखी गई है। हमारी जो नेपाली भाषा है उसकी लिपि देवनागरी है, हमारी लिपि के साथ उसका बहुत मेल खाता है। यदि यह स्थिति है तो हिन्दी को समृद्ध

[श्री आनन्द पांडे]

करने के लिए नेपाली जितनी सहायक हो सकती है हमारे संविधान के अंतर्गत दूसरी भाषा नहीं हो सकती है। हम समझते हैं हिन्दी को ही एक लिपि के रूप में नहीं बनना है क्योंकि यह तो कोई राजतान्त्रिक पद्धति नहीं होगी। अहिंसा अहिंसा जब हमारे देशवासी एक भाषा को वाल्यूटरी, स्वच्छा-पूर्वक स्वीकार कर लेंगे तब यह हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि देश की सब भाषाओं को मान्यता देनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, समृद्ध करना चाहिए। अभी यही बात बोल रहे हैं हमारे मंत्री महोदय भी बोल रहे हैं और हमारे दूसरे माननीय सदस्य भी बोल रहे हैं। जब हमारा यह मकसद होगा कि सभी भाषाओं को बढ़ावा देंगे, चाहे कितनी छोटी भाषा हो हम उसको समृद्ध करेंगे तो हमारी भावनात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता को जोरदार बल मिलेगा। अगर हम इस भाषा को मानेंगे उस भाषा को नहीं मानेंगे तो यह मेरे विचार में अन्याय होगा। ऐसा करने से हमारे देशवासियों को विशेष सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अगर किसी को सरकारी सर्विसेज की परीक्षाएं देनी हैं तो अगर जिस भाषा में परीक्षा देनी है उसका ज्ञान नहीं है तो उसको कठिनाई होगी। इसलिए मेरा विचार है कि अष्टम सूची को और विस्तार किया जाए और सभी प्रचलित भाषाओं को स्वीकार किया जाए जिससे किसी को रुकावट नहीं होगी। लेकिन जब तक यह नहीं होगा तब तक दूसरी भाषा जो समर्थ होगी, जिसमें सब गुण होंगे उसको इसमें अंतर्भुक्त करना ही होगा

*Time bell rings.*

अंत में मैं एक दो बात और कहूंगा। अभी हमको भाषायी अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देना है लेकिन उसके साथ ही हम को उन्हें देश की मेन-स्ट्रीम में शामिल भी करना है। वह भी हमारे इस देश के नागरिक है, वह भी देशभक्त है यह भावना जगाने के लिये विभिन्न जगहों में, विशेष करके पश्चिमी

बंगाल में, दार्जीलिंग के पहाड़ी इलाकों में जहां बहुसंख्यक नेपाली भाषा के लोग हैं उनको स्वायत्त शासन का अधिकार प्रदान करना चाहिए और उनके सामाजिक विकास के लिए उनकी यह स्वायत्त शासन की मांग को हमको मान लेना चाहिए। ऐसा होने से उनका संकोच दूर हो सकेगा और उन के मन में यह भावना आयेगी कि वह भी राष्ट्र के साथ और राष्ट्रीय प्रगति में भागीदार है। इसलिये पश्चिमी बंगाल में नेपाली भाषा-भाषी इलाकों में उनकी स्वायत्त शासन की मांग को स्वीकार किया जाये ताकि वे भी देश की मेन-स्ट्रीम के साथ आगे आकर, आगे बढ़ सकें और अपना विकास कर सकें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Most of the speakers are from the Congress Party. I think the time has to be restricted to 5 minutes. Otherwise, there is no time and the Minister has to reply.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) :

इतने महत्व का सवाल है और इस पर आप केवल पांच मिनट बोलने को कह रहे हैं।

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM (Andhra Pradesh): Sir, can you imagine that anybody could express himself in five minutes?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please sit down.

श्री कल्पनाथ राय : अधिष्ठाता महोदय,

यह भाषा का सवाल एक राष्ट्रीय सवाल है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please sit down, Mr. Kalp Nath. Why do you stand when I am standing? I am just saying that there is a long list. Because there is a long list—list after list is coming—it becomes necessary to reduce the time. But, if the House wishes to continue the debate on Wednesday also, I have nothing to say.

Therefore, please sit down... (*Interruptions*). Why do you get excited? I am just putting the whole thing before the House. There is a long list of Members. I can speak to your Whip also to see whether we could organise it that way. If it cannot be done,, then I cannot do anything. Anyway, we have to adjourn at 5 o'clock. If you can kindly co-operate with me, it can be done. Now, I will call Mr. Wajid.

श्री कल्पनाथ राय : इस पर पांच मिनट में अपनी बात नहीं कही जा सकती ।

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Sir, I was submitting... (*Interruptions*). If you are adjourning

(*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): It is not a question of my adjourning the House at my will. The House will be adjourned at 5 o'clock. If the discussion is to continue,, I have nothing to say about it. But you should not say that I have adjourned the House. It is not so. Because of the long list, I am just putting it before the House and it is for the honourable Members to decide. The Whip is here on this side and the Whip is there on that side also and, so, let them decide.

श्री कल्पनाथ राय : आदरणीय उप-सभाध्यक्ष महोदय, आप देखें कृपा करके यह बड़ा सवाल है और यह सवाल ऐसा नहीं है कि दो, तीन या पांच मिनट में इस पर बात कह दी जाय । इस पर पूरी डिबेट होनी चाहिए । इस लिये कृपा कर आप बोलने का हम लोगों को अवसर दें, वरना अभी बहस खत्म कर दें और हम लोग घर जायें ।

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Sir, it is such an important thing... (*Interruptions*). It is a subject of vital importance. You know that this is a subject on which many persons from this side and also from that side want to\* express their views. Sir,, suppose you were on your legs.

Would you have been satisfied if you were allotted only five minutes? This is such an important subject . . . (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): That is why I say that the whole thing is before the House.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: What I am submitting is that if the debate cannot be completed today, you have it tomorrow, because this is a very important subject. It is not that you can ask one person to express himself in such a short time...

(*Interruptions*)

श्री कल्पनाथ राय : सदन के नेता से मैं प्रार्थना करूंगा कि सदन का समय 6 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाये । इतनी मोटी रिपोर्ट पर कैसे बहस होगी । मैं इसलिए नेता सदन से प्रार्थना करूंगा कि सदन का समय बढ़ा दिया जाये ।

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Sir, these two Reports are bulky Reports. What for have they been circulated? What is the object of circulating them?

SHRI KALP NATH RAI: What is the object?

(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): One at a time, please. The Minister of State for Parliamentary Affairs is sitting now here and if you want, he can say something on this.

SHRI MOHAMMAD YUNUS SALEEM: Sir, what I am submitting is this... (*Interruptions*).. I would like to submit respectfully, Sir... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Please sit down. Is it your view that time should be extended till Wednesday?

DR. RAM KRIPAL SINHA: The Business Advisory Committee considered the matter and the leaders on the other side were also present. They agreed and decided that time allotted should be one day. So one day was allotted. On Wednesday we have another important subject, that is, Samachar,, that is going to be discussed. Now it is open to the Members. If they want to continue...

AN HON. MEMBER: You can extend it for one" hour at least.

श्री कल्पनाय राय : कृपया इसको बड़ा दीजिए, बहुत महत्व का सवाल है। श्रीमन, एक दिन के लिए हाउस अलाट हुआ और आज दो बजे यह शुरू हुई डिबेट, इस बीच में आन्ध्र का साइक्लोन आ गया, उस पर बहस होने लगी। यह राष्ट्रीय सवाल है।

DR. RAM KRIPAL SINHA: The Business Advisory Committee has allotted time of one day.

SHRI SIKANDER ALI WAJD: How many hours?

DR. RAM KRIPAL SINHA: One day...

(Interruptions)

श्री कल्पनाय राय : आदरणीय उपसभा-ध्यक्ष महोदय, समय बड़ा कि नहीं ?

DR. RAM KRIPAL SINHA: One day means up to 5 p.m. But if the House so desires, I have no objection in continuing for one hour more, up to 6 p.m.

इतने दिनों तक आप बहस में भी नहीं लाये, हमारी गवर्नमेंट ने तो इसको बहस में ला दिया।

(Interruptions)

श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी : श्रीमन, हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यकों की जिन्दगी का सवाल है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): We have already lost 5 minutes. I am requesting Dr. Ram Kripal Sinha and Mr.

Bipinpal Das to discuss the matter. By that time, let him speak. Yes, Mr. Sikander Ali Wajd.

श्री سکندر علی واجد : عالی

جذاب ذہنی چیورمین صاحب - یہ

رپورٹیں کانگریس کے زمانہ کی ہیں -

جن پر یہاں بحث ہو رہی ہے -

ایک اور رپورٹ اردو کے سلسلہ میں

دکھی ہوئی ہے - گجراتل کمیٹی کی

رپورٹ اس کو شائع نہیں کر رہے

ہیں - آپ اس کو شائع کر دیں -

دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ

اردو کے سلسلہ میں پارٹی کی بات

نہیں کر رہا ہوں - چلتا کی بات نہیں

کر رہا ہوں کانگریس کی بات نہیں کر

رہا ہوں - اس حمام میں سب ننگے

ہیں - تیس برس سے اردو کا مسئلہ

ایسے ہی پیش ہو رہا ہے - کانگریس

اردو والوں سے کہہ رہی تھی کہ اب

تصفیہ ہو جائیگا یہ ہو جائیگا وہ

ہو جائیگا - آپ کو کدستی تیوشن کی

دفعات ۲۹ ۳۲۵ ۳۲۷ ۳۵۰ دیکھلی

چاہئے - ہمارے ہوم منسٹر صاحب

نے ایک صحیفہ و غریب انٹرویو دیا

ہے - وہی ہوم منسٹر صاحب تو ہمارے

بوی ہیں - باہر کوئی نہیں پوچھے گا

کہ چلتا کے ہیں کہ کانگریس کے -

ایسی بات انہوں نے کی اردو کے بارے

میں کہ لوگ ہڈسہکے - تمہارے

چودھری صاحب نے یہ کہاں پوچھا

ہے کہ اردو ترکوں اور مغلوں کی

ہاں ہے -

میں ہندوستان نے بہت بڑے  
ہستورین ڈاکٹر تارا چند کی بات کہتا  
ہوں چلوں نے ہندوستان کی آزادی  
کی تاریخ چار جلدوں میں لکھی ہے۔  
انہوں نے 15 فروری 1958 کو فرمایا  
تھا جو ہندی رائج کی جا رہی ہے  
وہ بدیشی انگریزی سے زیادہ مشکل  
ہے۔ ہندوستان نے ایک تہائی کے  
قریب آبادی اس تہذیب کی پھر  
نہیں ہے جس کے ساختہ سکھت  
زبان میں ہیں۔ 1857 کے بعد  
انگریزوں نے اردو کو مسلمانی زبان بنا  
دیا۔ بہار کے گورنر نے شہروں کا دورہ  
کیا اور اردو کے خلاف دھواں دھار  
لیکچرس دیئے اور انگریزی کے عالموں  
نے ہندوستان کی زبان میں گرامر  
لکھی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش  
کی کہ اردو کسی علاقہ کی زبان  
نہیں ہے۔ ہماری فکشنری میں ہے کہ  
۷۵ فی صدی لفظ ہندی کے ہیں۔  
کریٹوسن اور چتر جی یہ فوٹالوجسٹ  
ہوں۔ دونوں مانتے ہیں کہ کڑی  
بولی سے پہلے اردو کی ادبی زبان نکلی۔  
اس کے کئی سو سال بعد انیسویں  
صدی میں اسی بولی سے ادبی ہندی  
نے جنم لیا۔ ہندوستان کی چودہ  
زبانوں میں اردو اکھلی ایسی زبان  
ہے جو ہندوستان کی روایتوں کی  
ترجمانی کرتی ہے۔ انہوں کی دفعہ  
۳۲۷ کے تحت ہر ریاست میں اسکو  
سرکاری زبان کا درجہ ملنا چاہئے۔ اس  
لئے کہ دنیا میں زیادہ تر ملک ایسے

ہیں جہاں دو یا دو زبانوں کو سرکاری  
سطح پر تسلیم کیا گیا ہے۔ مجھے  
آپ کا بیان سن کہ ایک انگریزی  
جملہ یاد آتا ہے۔  
Audacity of the Ignorant.

جاہل کی جسارت—انہوں نے اس  
جسارت کا ثبوت دیا جس سے سب  
تلگ ہیں۔ ایک بات میں کہہ دوں کہ  
جلتا کے لہندوں کے بارے میں وہ صاف  
بات کہتے ہیں چاہے کسی بھی ہو۔  
نتیجہ یہ ہوا کہ اردو والے جو خوش  
فہمی میں تھے وہ دور ہو گئی۔  
کانگریس نے اس کے لئے کچھ زیادہ  
نہیں کیا۔ مگر آپ تو کہتے ہیں کہ  
کرپلے بھی نہیں۔ آپ نے صاف کر  
دیا اس مسئلے کو۔ مجھے خوشی ہے  
ہم کر کچھ اسد تھی کانگریس والوں  
سے لیکن اب وہ اسد بھی مت گئی۔  
آپ نے صاف کر دیا کہ چار چہ  
مہولے ہی میں کہ اردو کا کوئی مقام  
نہیں ہے۔ یہ بے کار ہے دستور یا انہوں  
جو بنایا ہے۔ مراد جی بھی کہتے  
ہوں اور چونہری چرن سنگھ  
بھی بھی کہتے ہیں۔ ہمارے انہوں  
میں اردو کو جو حق دیا گیا ہے  
وہ نہیں ملتا ہے۔ تسلیم کا سوال  
بعد میں آتا ہے۔ ایک اور ہندو  
لیڈر تھے جو گاندھی جی کے  
بعد آئے اور ہمارے دل میں بہت  
ان کی عزت ہے۔ وہ صاف بات کرتے

[شری سکندر علی وحید]

نہ کبھی بات کرتے تھے وہ راجہ جی  
ہیں - راجہ جی نے ۶ جنوری  
۱۹۷۱ کو کہا تھا وہ اردو کے ساتھ  
بڑی بے انصافی ہوئی ہے اور یہ  
بے انصافی ہمارے دامن پر بڑا دھبہ ہے  
داخل ہے یہ اسمبلی کا فیصلہ گاندھی  
جی کی منشا کے خلاف ہے - کانگریس  
کی تجاویز کے خلاف ہے - اتنے بڑے  
ملک کے لئے جو روس کو چھوڑ کر  
یورپ کے برابر ہے قطعی نامناسب  
ہے دنیا میں ۴۳ سے زیادہ ملک  
ایسے ہیں جن کی دو یا تین سرکاری  
زبانیں ہیں - سوئزرلینڈ کتنا چھوٹا  
سا ملک ہے لیکن اس میں چار  
زبانیں ہیں - فرینچ - جرمن -  
اطالوی - رومانیہ یہ سرکاری زبانیں  
ہیں - اس میں رومان کے ۵۰  
ہزار سے زیادہ بولنے والے نہیں ہیں -  
میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی  
چودہ زبانوں کو سرکاری زبان کا درجہ  
ملنا چاہئے - گاندھی جی نے ہندوستانی  
کی زائید کی تھی - گاندھی جی کے سارے  
جانے سے زبان کا سوال نہیں مڑ گیا -  
یہ پھر ابھرے گا - اردو دیس کی  
چھٹی زبان ہے - چار کروڑ لوگ اس  
کے بولنے والے ہیں - میں ابک بات  
آپ سے کہوں گا - شاہ عالم بہادر شاہ  
کو جب غلام قادر روہیلے نے اندھا کر  
دیا تو مادھو جی سندھیا نے انہیں  
ایلی پلاہ میں لے لیا - اسی موقع

پر مجھے شاہ عالم کا ایک شعر یاد  
آتا ہے - مادھو جی سندھیا فرزند جگر  
بلد من هست - یہ مہری لوالہ کے  
برابر ہے - مہری حفاظت کر رہا ہے  
آج اردو کا یہی حال ہے اردو کو مرہٹے  
پال رہے ہیں - اردو کے لئے کوئی اور  
بولنے کے لئے تیار نہیں ہے - صرف  
مہاراشٹر میں اردو کے اتنے کالج اور  
اتنے ٹیچر ہیں جتنے سارے ہندوستان  
میں نہیں ہیں - اردو کے متعلق  
ان کا دماغ صاف ہے انہیں اپنی  
زبان پسند ہے لیکن وہ اردو کو بھی  
ہندوستان کی زبان مانتے ہیں اردو  
کا جنم یہیں ہوا ہے اور مراثی کا  
بھی جنم یہیں ہوا ہے - مہاراشٹر  
میں ہمیں کچھ اور شکایتیں ہیں  
لیکن زبان کے معاملہ میں مہاراشٹر  
کا رویہ صاف ہے - ہماری جو اردو  
اکادمی ہے اس کے صدر ہمارے چیف  
منسٹر بسنت دادا پاتل ہیں لیکن  
آپ کی یو - پی میں اردو اکادمی  
ٹوٹ گئی ہے وہاں کے لوگوں نے ریڑائن  
کو دیا ہے اور اس میں اب ہندی  
والے بھرتی ہو رہے ہیں وہ بھی ختم  
ہو جائیگی - میں چاہتا ہوں کہ  
ہندوستان کی چودہ زبانوں کی طرح  
اردو کو بھی حق دیا جائے - مجھے  
بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے جب  
میں بڑے بڑے ذمہ دار منسٹروں کے  
بیانات اور تقریریں اردو کے مسئلہ پر  
پڑھتا ہوں - جو سب لوگ یہاں

بہتے ہوئے ہیں اس بات کو جاننے  
ہیں کہ جو بیانات اور تقریریں نکلتی  
ہوں ان کو کسی نے کنٹرولنگت نہیں  
کیا ہے - یہ چودھری چرن سنگھ کا  
انترویو ہے اور انہوں نے اپنے علم کا اس  
میں اظہار کیا ہے - میں کہتا ہوں  
کہ کم سے کم باہر کے ملکوں میں تو  
آپ اپنے کو بدنام نہ کھجئے ہندوستان  
کی تاریخ میں اردو کی کیا جگہ ہے  
اس بات سے ہندوستان کے لوگ  
اور انگلستان کے لوگ سبھی واقف  
ہیں مگر اب ایک بات صاف ہوگئی  
کہ آپ لوگوں نے زبان کا مسئلہ صاف  
کر دیا - اب اردو والوں کو کوئی  
غلط فہمی نہیں رہی چاہئے - میں  
اردو والوں سے کہتا ہوں کہ بھائی  
کھراؤ نہ کرو نہ کوئی سٹیج کرہ کرو  
اور نہ کوئی ایسا کام کرو جو قانون کے  
خلاف ہو لیکن ابھی الیکشن آ رہا ہے  
جن لوگوں نے کانگریس کو کرسی پر  
بٹھایا تھا انہیں لوگوں نے کانگریس کے  
خلاف ایذا ورت دیا کیوں کہ کانگریس  
نے اردو کے ساتھ انصاف نہیں کیا -  
اب آپ لوگ آئے ہوں اور آپ نے  
اس طرح کے اعلان کئے ہیں اس لئے  
آپ لوگ بھی نہیں رہیں گے - آپ کی  
پالیسی کیا ہے یہ بات ہداری سمجھ  
میں نہیں آتی کسی نے تھک ہی  
کہا ہے کہ انوس منسٹر نہیں ہوں  
انوس پرائم منسٹر ہیں - ہر آدمی  
کا ایذا دماغ ہے اور ہر آدمی  
پالیسی ڈیکلریشن دیتا رہتا ہے - کچھ

لوگ کہتے رہتے ہوں ارے بھئی یہ  
بات نہیں ہے لیکن میں کہتا چاہتا  
ہوں کہ اردو کے بارے میں اگر پرائم  
منسٹر کی بات نہ مانتے تو پھر کس  
کی بات مانتے - چودھری چرن سنگھ  
جو ہم منسٹر ہیں ان کی بات نہ  
مانتے تو کیا پھر آپ کی بات مانیں ؟  
انہوں نے خود یہ باتیں کہی ہیں -  
زبان کے ماننے نہ ماننے کا سوال نہیں  
ہے - اس میں ہندی والوں کی  
منظوری کا بھی سوال نہیں ہے یہ کہہ  
دیا جاتا ہے کہ ۸۵ فی صدی ہندی  
والے ہیں اگر وہ اردو نہیں مانتے گے  
تو کس طرح اردو ہو - پی کی سرکاری  
زبان بن سکتی ہے یہ ہندی والوں کا  
سوال نہیں ہے وہ تو قیامت تک بھی  
نہیں مانتے گے - ان کے سرپرست تو  
آپ یہاں بہتے ہوئے ہیں - ل یہ  
ہے کہ آپ کلسٹی ٹیوشن کی ۳۴۷  
ویں دفعہ بھی نہیں پڑھ سکتے  
ہیں - چودھری چرن سنگھ اگر اس  
کو نہیں سمجھ سکتے تو ان کے  
پاس تو بڑے بڑے لائق لوگ  
ہوں سیکریٹریز ہوں جو قانون کے  
ماہر ہوں ان سے اس دفعہ کے  
معلیٰ آپ سمجھ سکتے ہیں -  
چودھری چرن سنگھ کو بھی اب  
ایذا حساب دینا پڑے گا - اب تک  
سب سے حساب لیا گیا ہے - زبان  
کے معاملے میں کانگریس سے بھی  
ہم نے حساب لیا ہے -



[شری سکندر علی وجد]

تو سب سے بڑے محکمے  
ہیں - ایک موم منسٹری - ایک  
انفارمیشن اینڈ پراڈکسٹنگ منسٹری  
اور ایک ایجوکیشن منسٹری ہے -  
ان تینوں نے مل کر اردو کو بہانہ  
کیا ہے - مجھے یاد ہے کہ کلسٹریٹو  
کمیشن کی میٹنگ میں جس  
میں گجراٹ صاحب اور دوسرے  
یورپس کے لوگ بھی شامل تھے -  
اندراجی نے موری بات چیت ہوئی  
تھی میں نے ان سے کہا کہ ہم  
آپ سے اردو کی تعریف ملتے ملتے  
تھک گئے اب اس کے لئے کچھ  
گجراٹ صاحب نے کہا کہ اردو ایک  
بڑی زبان ہے - ہماری حکومت اس  
کو آگے بڑھانے کی کوشش میں ہے  
اندراجی سے کہا کہ آپ کا حکم  
ہر محکمے میں چلتا ہے صرف  
ریڈیو کے ڈیپارٹمنٹ اور انفارمیشن  
اور پراڈکسٹنگ کے محکمے میں نہیں  
چلتا - گجراٹ صاحب نے کہا کہ اردو  
کے ساتھ ایک تاریخی لٹریچر ہے  
وجد صاحب جو اعتراض کر رہے  
ہیں وہ صحیح ہے - بھائی ہم تو  
کسی کو نہیں بخشیں گے - اس لئے  
نہیں کہ اردو موری زبان ہے - میں  
اس کا شاعر ہوں - بلکہ اس لئے کہ  
یہ ہندوستانی زبان ہے -

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Wajd., I think you have to stop now.

[شری سکندر علی وجد : دو]

مذمت اور لوں گا - میں اردو کا  
آدمی ہوں - میں جو بات کہہ رہا  
ہوں وہ سچ سمجھ کر کہہ رہا  
ہوں - ہمارے پاس غالب اور اقبال  
بڑے شاعر ہیں - میں نے غالب  
کا دیوان دیوناگری میں لکھا ہے  
ایک ساوتھ انڈین سے پوچھایا - میں  
ان سے ہندی پوچھتا تھا - انہوں نے  
یوں پوچھا -

کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے -  
وہ فکر جس میں ہے پروردہ روح کرانی -  
† [کسے کہہ کر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے  
وہ پھر جس میں ہے پروردہ روح کرانی]

میرے مہلتے غزل میں تھی سراسر باری  
شیخ کہتا ہے کہ یہ بھی ہے حرام اے سنی  
† [میری مہلتے گجراٹ میں نہیں جراسی باکی  
شیکہ کہتا ہے کہ یہ بھی ہے حرام اے سنی]

ع کیا وہ سرود کی خدائی تھی -  
† [کہا وہ سرود کی کھدائی تھی -]  
نہ تھا کچھ تو خدا تھا - کچھ نہ  
ہوتا تو خدا ہوتا

† [نہ تھا کچھ تو خدا تھا - کچھ نہ ہوتا  
تو خدا ہوتا -]

ایک شعر اقبال کا ہے - آپ اردو  
سمجھتے ہو گئے - سبھی ہندی والے

اردو سمجھتے ہیں - جھوٹ بولتے  
 ہیں کہ نہیں سمجھتے -  
 اگر کہو گیا ایک شخص تو کیا ہم -  
 مقامات آہ و فغاں اور بھی ہوں -  
 اگر کہو گیا ایک شخص تو کیا ہم  
 مقامات آہ و فغاں اور بھی ہوں -  
 تو میں یہ کہتا ہوں کہ خط کے  
 ساتھ زبان کا گہرا تعلق ہے اور جواہر لال  
 نہرو نے اپنی اتھ گرافی میں لکھا ہے -  
 ہر زبان کی ایک لہری یعنی ایک رسم  
 الخط ہوتا ہے لہوں کے ساتھ زبان کا  
 جسم و جان کا تعلق ہوتا ہے - جب  
 لہری بدل جاتی ہے تو لفظ بھی بدل  
 جاتے ہیں ان کی شکل بدل جاتی ہے  
 اور ان کے معنی بدل جاتے ہیں  
 آج پلڈت جواہر لال نہرو تو آؤتے  
 قہقہہ ہو گئے - اب حالات بدل گئے  
 ہیں - پہلے جو لوگ یہاں رہتے تھے  
 وہ آج ملنگر ہو گئے - اردو کا ایک  
 شعر ہے -  
 ایسے دہسے کہسے کہسے ہو گئے -  
 کہسے کہسے اہسے دہسے ہو گئے -  
 اردو بڑی مشکل زبان ہے جسے سمجھ  
 ہوتی ہے شام ہوتی ہے - عمر بونہی  
 تمام ہوتی ہے -  
 میں نے ۲۰ سال پہلے میں اچلتا پر  
 نظم لکھی اور ۱۰ برس میں ایلورا پر  
 نظم لکھی کہا اچلتا اور ایلورا ہندی  
 والوں نے نہیں دیکھے تھے

[t] Hindi pronunciation.

श्री श्रीकान्त वर्मा (मध्य प्रदेश) : मैं  
 उर्दू के फेवर में बोनने वाला हूं। आप  
 हिन्दी का मखोल उड़ा रहे हैं। यह उचित  
 नहीं। उर्दू से हिन्दी का कोई झरड़ा नहीं  
 है।

श्री सिकन्दर علی وجد : مخالفت

کی بات نہیں ہے - جو دوسرے کی زبان  
 کی عزت نہیں کرنا وہ اپنی زبان  
 کی بھی عزت نہیں کرتا - میں کسی  
 زبان کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں -  
 آپ نے میں اتنا عرض کرنا چاہتا  
 ہوں کہ جو اردو کا حق ہے جو اس کو  
 قانون نے دیا ہے جو دستور کے دیا ہے  
 وہ آپ اس کو دیکھئے - اردو والے آپ  
 کی سرپرستی آپ کی مہربانی نہیں  
 چاہتے صرف انصاف چاہتے ہیں -  
 مجھے امید ہے آپ اپنے بزرگ مراچی  
 قہسائی اور عالم فاضل چون سلکچچی  
 کو بھی یہ بات سمجھا دیں گے - یہ  
 فلسفے کی بات نہیں ہے - میں  
 کہوں گا کہ مہری بات اگر انہیں ناہسلد  
 ہے تو غصہ کر سکتے ہیں لیکن یہ  
 فلسفہ کا موقعہ نہیں ہے -

[श्री सिकन्दर अली वज्ज : आली  
 जनाव डिप्टी चेयरमैन साहब, ये रिपोर्ट  
 कांग्रेस के जमाने की है जिन पर यहां बहस  
 हो रही है—एक और रिपोर्ट उर्दू के सिल-  
 सिले में रखी हुई है, गुजराल कमेटी की  
 रिपोर्ट। उसको शायी नहीं कर रहे हैं।  
 आप उसको शायी कर दें। दूसरी बात  
 मुझे यह कहनी है कि उर्दू के सिलसिले में,  
 मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जनता]

[t] Devanagari transliteration.

## [श्री सिकन्दर अली बख्त]

की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। इस हमाम में सब तंगे हैं। 30 बरस से उर्दू का मसला ऐसे ही पेश हो रहा है। कांग्रेस उर्दू वालों से कह रही थी कि अब तस्फीया हो जाएगा, ये हो जाएगा, वे हो जाएगा। आपको कांस्टीट्यूशन की दफात 29 या 345, 347, 350 देखनी चाहिये। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक अजीबो-गरीब इंटर-यू दिया है। वही होममिनिस्टर साहब तो हमारे भी हैं — बाहर कोई नहीं पूछेगा कि जनता के हैं या कांग्रेस के हैं। ऐसी बात उन्होंने उर्दू के बारे में की लोग हंसेंगे। तुम्हारे चौधरी साहब ने यह कहा पड़ा है कि उर्दू तुर्कों और मुगलों की जवान है। मैं हिन्दुस्तान के बहुत बड़े हिस्टोरियन डा० ताराचन्द की बात कहता हूँ जिन्होंने हिन्दुस्तान की आजादी की तारीख चार जिल्दों में लिखी है — उन्होंने 15 फरवरी, 1958 को फर्माया था जो हिन्दी राज की जा रही है वह विदेशी अंग्रेजी से ज्यादा मुश्किल है। हिन्दुस्तान की एक तिहाई के करीब आबादी उस तहजीब की पैरो नहीं है जिसके माखज संस्कृत जवान में है। 1857 के बाद अंग्रेजों ने उर्दू को मुस्लमानी जवान बना दिया। बिहार के गवर्नर ने शहरों का दौरा किया और उर्दू के खिलाफ धुआंधार लेक्चर दिए और अंग्रेजी के आलिमों ने हिन्दुस्तान की जवान में ग्रामर लिखी है और ये साबित करने की कोशिश की है कि उर्दू किसी इलाके की जवान नहीं है। हमारी डिक्शनरी में 75 फीसदी लब्ज हिन्दी के हैं। ग्रसन और चटर्जी ये फिलालोजिस्ट हैं। दोनों मानते हैं कि खड़ी बोली से पहले उर्दू की अदबी जवान निकली। इसके कई सौ साल बाद उन्नीसवीं सदी में इस बोली से अदबी

हिन्दी ने जन्म लिया। हिन्दुस्तान की चौदह जवानों में उर्दू अकेली ऐसी जवान है जो हिन्दुस्तान की रियायतों की तर्ज-मानी करती है। आईन की दफे 347 के तहत हर रियायत में उसको सरकारी जवान का दर्जा मिलना चाहिये। इसलिए कि दुनिया में ज्यादातर मुल्क ऐसे हैं जहां दो या तीन जवानों को सरकारी सतह पर तस्लीम किया गया है। मुझे आपका बयान सुनकर अंग्रेजी जमला याद आता है।

## Audacity of the ignorant

जाहिल की जिसारत — उन्होंने इस जिसारत का सबूत दिया जिससे सब तंग हैं। एक बात मैं कह दूँ जनता के लीडरों के बारे में वो साफ बात कहते हैं चाहे कैसी भी हो। नतीजा यह हुआ कि उर्दू वाले जो खुशफहमी में थे वो दूर हो गई। कांग्रेस ने उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं किया। मगर आप तो कहते हैं कि करेंगे भी नहीं आपने साफ कर दिया इस मसले को। मुझे खुशी है। हमको कुछ उम्मीद थी कांग्रेस वालों से अब तो वो उम्मीद भी मिट गई। आपने साफ कर दिया चार छ. महीने ही में कि उर्दू का कोई मुकाम नहीं है — ये बेकार है। दस्तुर या आईन जो बनाया है — मोरारजी भी यही कहते हैं और चौधरी चरण सिंह भी यही कहते हैं हमारे आईन में उर्दू को जो हक दिया गया है वह नहीं मिलता है। तालीम का सबाल बाद में आता है। एक और हिन्दू लीडर थे जो गांधी जी के बाद आये और हमारे दिल में बहुत उनकी इज्जत है। वो साफ बात करते थे, खरी बात करते थे वह राजाजी हैं। राजाजी ने 6 जनवरी, 1971 को कहा था कि उर्दू के साथ बड़ी बेइन्साफी हुई है और यह बेइन्साफी हमारे

दामन पर बड़ा धक्का है, दाग है—यह असेम्बली का फैसला गांधी जी की मन्शा के खिलाफ है। कांग्रेस की तजवीज के खिलाफ है। इतने बड़े मुल्क के लिए जो रूस को छोड़कर पूरे यूरोप के बराबर है कतई नामुनासिब है। दुनियां में 43 से ज्यादा मुल्क ऐसे हैं जिनकी दो या तीन सरकारी जुबानें हैं। स्विट्जरलैण्ड कितना छोटा सा मुल्क है लेकिन उसकी चार जुबानें हैं। फ्रेंच, जर्मन, इतालवी और रोमांश—ये सरकारी जुबानें हैं। इसमें रोमानश के 50 हजार से ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की चौदह जुबानों को सरकारी जुबान का दर्जा मिलना चाहिये। गांधी जी ने हिन्दुस्तानी की ताईद की थी। गांधी जी के मारे जाने से जुबान का सवाल नहीं मर गया। यह फिर उभरेगी। उर्दू देश की छठी जुबान है। चार करोड़ लोग इसके बोलने वाले हैं—मैं एक बात आपसे कहूँगा—शाह आलम बहादुरशाह को जब गुलाम कादिर रोहिल्ले ने अन्धा कर दिया तो माधोजी सिंधिया ने उन्हें अपनी पनाह में ले लिया। इस मौके पर मुझे शाह आलम का एक घोर याद आ रहा है। “माधो जी सिंधिया पारजद जियर बन्देमन हस्त”। ये मेरी आलाद के बराबर हैं, मेरी हिफाजत कर रहा है आज उर्दू का यही हाल है उर्दू को मरहटे पाल रहे हैं उर्दू के लिए कोई और बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ महाराष्ट्र में उर्दू के इतने कालिज और इतने टीचर्स हैं जितने सारे हिन्दुस्तान में नहीं हैं। उर्दू के मुत्तलक उनका दिमाग साफ है। उन्हें अपनी जुबान पसन्द है लेकिन वे उर्दू को भी हिन्दुस्तान की जुबान मानते हैं। उर्दू का जन्म यहीं हुआ है और मराठी का भी जन्म यहीं हुआ है। महाराष्ट्र में हमें कुछ और शिकायतें हैं लेकिन जुबान के मामले में महाराष्ट्र का खैया

साफ है। हमारी जो उर्दू एकेडमी है उसके सदर हमारे चीफ मिनिस्टर बसन्त दादा पाटिल हैं लेकिन आपकी यू० पी० में उर्दू एकेडमी टूट गई है। वहाँ के लोगों ने रिजाइन कर दिया है और उसमें अब हिन्दी वाले भरते हो रहे हैं। वे भी खत्म हो जायेंगी। मैं चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की 14 जुबानों की तरह उर्दू को भी हक दिया जाये। मुझे बड़ा अफसोस और दुःख होता है जब मैं बड़े बड़े जिम्मेदार मिनिस्टरों के बयानात और तक्रीरें उर्दू के मसलों पर पढ़ता हूँ। जो सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस बात को जानते हैं कि जो बयानात और तक्रीरें निकलती हैं उनको किसी ने कंट्रिब्यूट नहीं किया है। ये चौधरी चरण सिंह का इंटरव्यू है और उन्होंने अपने इल्म का इसमें इजहार किया है। मैं कहता हूँ कि कम से कम बाहर के मुल्कों में तो आप अपने को बदनाम न कीजिये। हिन्दुस्तान की तारीख में उर्दू की क्या जगह है? इस बात से हिन्दुस्तान के लोग और इंगलिस्तान के लोग सभी बाकिफ हैं अगर अब एक बात साफ हो गई कि आप लोगों ने जुबान का मसला सफ कर दिया। अब उर्दू वालों को कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। मैं उर्दू वालों को कहता हूँ कि भई घेराव न करो न कोई सत्याग्रह करो और न कोई ऐसा काम करो जो कानून के खिलाफ हो लेकिन अभी इलेक्शन आ रहा है जिन लोगों ने कांग्रेस को कुर्सी पर बिठाया था उन्हीं लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ अपना वोट दिया क्योंकि कांग्रेस ने उर्दू के साथ इन्साफ नहीं किया अब आप लोग आये हैं और आपने इस तरह के एलान किये हैं इसलिये आप लोग भी नहीं रहेंगे। आपकी पालिसी क्या है ये बात हमारी समझ में नहीं आती। किसी ने ठीक ही कहा है कि उन्नीस मिनिस्टर नहीं हैं उन्नीस प्राइम मिनिस्टर हैं। हर आदमी का अपना दिमाग है और हर आदमी पालिसी डिक्लेरेशन देता रहता है। कुछ लोग कहते रहते हैं अरे भई यह बात नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूँ

[श्री सिकन्दर अली वज्ज]

कि उर्दू के बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर की बात न मानें तो फिर किसकी बात मानें। चौधरी चरण सिंह जो होम मिनिस्टर हैं उनकी बात न मानें तो क्या फिर आपकी बात मानें? उन्होंने बुद ये बातें कही हैं। जुवान के मानने न मानने का सवाल नहीं है। इसमें हिन्दी वालों की मंजूरी का भी सवाल नहीं है। ये कह दिया जाता है कि 95 फोसदी हिन्दी वाले हैं। अगर वो उर्दू नहीं मानेंगे तो किस तरह उर्दू यू० पी० की सरकारी जुवान बन सकती है। यह हिन्दी वालों का सवाल नहीं है वह तो क्यामत तक भी नहीं कहेंगे। उनके सरपरस्त तो आप यहां बैठे हुए हैं सवाल यह कि आर कांस्टीट्यूशन की 347 वीं दफा भी नहीं पढ़ सकते हैं। चौधरी चरण सिंह अगर इसको नहीं समझ सकते तो उनके पास तो बड़े बड़े लायक लोग हैं सेक्रेटरीज हैं जो कानून के माहिर हैं उनसे इस दफे के मायने आप समझ सकते हैं। चौधरी चरण सिंह को भी अब अपना हिमाब देना पड़ेगा। अब तक सबसे हिसाब ले लिया गया है। जुवान के मामले में कांग्रेस से भी हमने हिसाब लिया है।]

तीन सबसे बड़े महकमे हैं। एक होम मिनिस्टरों, एक इनफार्मेशन एंड ब्राड-कास्टिंग मिनिस्टरों और एक एजुकेशन मिनिस्टरों है। इन तीनों ने मिल कर उर्दू को बर्बाद किया है। मुझे याद है कि कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में जिसमें गुजराल साहब और दूसरे प्रेस के लोग भी शामिल थे इन्दिरा जी से मेरी बातचीत हुई थी। मैं ने उनसे कहा कि हम आपसे उर्दू की तारीफ सुनते सुनते थक गये। अब उसके लिए कुछ कीजिए। गुजराल साहब ने कहा कि उर्दू एक बड़ी जुवान है हमारी हकूमत उसको आगे बढ़ायेगी लेकिन मैंने इन्दिराजी से कहा कि आपका हुक्म हर महकमे में चलता है सिर्फ रेडियो डिपार्टमेंट में और इनफार्मेशन ब्राडकास्टिंग के महकमे में

नहीं चलता है। गुजराल साहब ने कहा कि उर्दू के साथ एक तारीबी लीगेसी है। वज्ज साहब जो इतराज कर रहे हैं वो सही है। भई हम तो किसी को नहीं ब्रखते। किसी को नहीं ब्रखेंगे इसलिए नहीं कि उर्दू मेरी जुवान है। मैं इसका शायर हूँ बल्कि इसलिए कि यह हिन्दुस्तानी जुवान है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Wajid, I think you have to stop now.

श्री सिकन्दर अली वज्ज : दो मिनट और लूंगा। मैं उर्दू का आदमी हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ वह सोच समझ कर कह रहा हूँ। हमारे पास गालिब और इकबाल बड़े शायर हैं। मैंने गालिब का दीवान देवनागरी में लिखा हुआ एक साउथ इण्डियन को पढ़ाया। मैं उनकी हिन्दी पढ़ता हूँ

[किसे खबर कि हजारों मुकाम रखता हूँ—  
वो फिर जिसमें है बेपर्दा रूह कुरानी।

किसे खबर कि हजारों मुकाम रखता है।  
वह फिर जिसमें है बे परदा रूह कुरानी है।]

दूसरा शेर है—

[मेरे मीनाये गजल में थी जरा सी बाकी  
शेख कहता है कि ये भी है हराम ऐ साकी  
मेरी मीनाये गजल में थी जरासी बाकी।  
शेख कहता है कि यह भी है हराम ऐ साकी।]  
क्या वो नमरुद की खुदाई थी—  
क्या वो नमोरद की खुदाई थी  
न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता  
न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता

एक शेर इकबाल का है। आप उर्दू समझते होंगे। सभी हिन्दी वाले उर्दू समझते हैं। झूठ बोलते हैं कि नहीं समझते;

अगर खो गया एक नशेभन,  
तो क्या गम मुकामाते आहो  
फगा और भी है।  
अगर खो गया एक नशेभन,  
तो क्या गम  
मुकामात आहो फगा और भी है।]

तो मैं यह कहता हूँ कि खत के साथ जुबान का गहरा ताल्लुक है जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आटोबाईग्राफी में लिखा है। हर जुबान की एक लिपि यानि एक रस्म-उलखत होता है। लिपि के साथ जुबान का जिस्मोजान का ताल्लुक होता है। जब लिपि बदल जाती है तो लफ्ज बदलते हैं और उनकी शकल बदल जाती है और उनके मायने बदल जाते हैं। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू तो आऊट डेटिड हो गये अब हालात बदल गये हैं। पहले जो लोग यहां बैठते थे वो आज मिनिस्टर हो गये हैं। उर्दू का एक शेर है—

ऐसे बैसे कैसे कैसे हो गये  
कैसे कैसे ऐसे बैसे हो गये।

उर्दू बड़ी मुश्किल जुबान है जैसे सुबह होती है शाम होती है। उधर यू हो तमाम होती है। मैंने 20 साल में अजंता पर नज्म लिखी और 10 बरन में एलोरा पर नज्म लिखी क्या अजंता और एलोरा हिन्दी बालो ने नहीं देखे थे ?

श्री श्रीकान्त वर्मा : मैं उर्दू के फेवर में बोलने वाला हूँ। आप हिन्दी की मखौल उड़ा रहे हैं। यह उचित नहीं। उर्दू का हिन्दी का कोई झगड़ा नहीं है।

श्री सिकन्दर अली वज्जद : मुखालफत की बात नहीं है। जो दूसरे के जुबान को इज्जत नहीं करता वो अपनी जुबान की भी इज्जत नहीं करता। मैं किसी जुबान की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ आप से मैं इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि जो उर्दू का हक है जो इसको कानून ने दिया है जो दस्तूर ने दिया है वो आप इसको दीजिये। उर्दू वाले आपकी सरपरस्ती आपकी महारानी नहीं चाहते—सिर्फ ईसाफ चाहते हैं। मुझे उम्मीद है आप अपने बुजुर्ग श्री मोरारजी देसाई और आलम फाजल चरण सिंह जो की भी यह बात समझा देंगे। ये हंसने की बात नहीं है। मैं कहूंगा कि मेरी बात अगर इन्हें नापसन्द है तो गुस्सा कर सकते हैं लेकिन यह हंसने का मौका नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Now, before I call the next speaker, I may inform the House that it has been agreed that the House will sit beyond 5.30 and the Minister will reply at 5.30. This has been agreed to between the two Whips. So, I now call Mr. Shrikant Verma. I am allowing 8 to 10 minutes, otherwise, we would not be able to finish by that time.

SHRI SHRIKANT VERMA: Yes, I would not take even that much time.

उपसभाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ मुझे श्री सिकन्दर अली वज्जद साहब का जो टोन था वह पसन्द नहीं आय ...

(Interruptions) उसमें थोड़ा यह लगा जैसे कि हिन्दी और उर्दू के बीच कोई झगड़ा है या हिन्दी एक इनफीरियर भाषा है ऐसी कोई बात नहीं है।

मैं उर्दू के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सारा समय मैं उर्दू के पक्ष में ही बातें कहना चाहता हूँ। उपसभाध्यक्ष महोदय, उर्दू के बारे में एक मसल है, आती है उर्दू जवां आते आते। और 300 साल में हिन्दुस्तान में एक बहुत उम्दा और नफ़ीस जुबान बनी जिसको कि उर्दू का नाम दिया गया और इस भाषा ने बहुत बड़े शायर और कवि पैदा किये गालिव, भीर, सौदा, और इक़बाल। और इस भाषा के साहित्य की परम्परा पर हम सबको नाज़ है। जिन्हें नाज़ नहीं है उनको भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उर्दू इस देश की भाषा है, उसकी जबरदस्त परम्परा है। आज अगर हिन्दी भाषा एक जिन्दा भाषा है तो इसका श्रेय उर्दू को भी है क्योंकि उर्दू ने हिन्दी को भी किसी हद तक प्रभावित किया है, मार्टन हिन्दी को। मैं हिन्दी का कवि और लेखक हूँ। मैं जो जुबान लिखता हूँ या इस सदन में भी जो कुछ बोलता हूँ उस पर उर्दू का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। सबसे पहले तो मैं उपसभाध्यक्ष महोदय 14 जुलाई, 1958 को भारत सरकार

[श्री श्री कान्त वर्मा]

ने लैन्ग्वेज पर, भाषा पर जो वक्तव्य दिया था, उसे ही पूर्वाग्रह पर आधारित मानता हूँ। उसमें उर्दू को, उस स्टेटमेंट में एवेरियेशन आफ हिन्दी बताया गया है। लेकिन मैं इसे ठीक नहीं मानता। मैं यह नहीं मानता कि उर्दू जबान केवल एक वेरियेशन है हिन्दी का क्योंकि उर्दू वाले भी कह सकते हैं और कहते रहे हैं कि हिन्दी उर्दू का वेरियेशन है इसलिए इस विवादास्पद सवाल पर तटस्थ दृष्टिकोण न अपना कर पक्षधर दृष्टिकोण अपना कर भारत सरकार के गृह मन्त्रालय ने गलती की थी और उसके बाद उसी स्टेटमेंट में काफी कुछ लीपा-पोती की गई और यह बताया गया कि उर्दू की तरक्की के लिए यह सब किए जाएंगे। लेकिन बुनियादी सवाल से उसी समय कतरा दिया गया और वह बुनियादी सवाल यह था कि जब तक उर्दू उसी तरह प्रशासन की भाषा नहीं बनती जिस तरह कि हिन्दी या कोई और भाषा तब तक उसकी तरक्की नहीं हो सकती। उपसभाध्यक्ष महोदय, केवल लेखकों, साहित्यकारों को कुछ अवार्ड देने से कुछ किताबों की उम्दा जिल्द छप जाने से कुछ लाइब्रेरियों में कुछ शेरो-शायरी की, किताबें पहुँचा देने से किसी जबान को मान्यता नहीं मिलती। उसको मान्यता मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में। जब तक वहाँ मान्यता नहीं मिलती तब तक लोग अपने बच्चों का भविष्य अंधकारमय मानेंगे। मैं तो इस मामले में हिन्दी के लिए भी यही कहूँगा। लोग आज हिन्दी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजने के बजाय अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हैं उस का भी यही कारण है। वे सोचते हैं कि अंग्रेजी हटने वाली नहीं है और हिन्दी का भविष्य अंधकारमय है। इसलिए बच्चों को हिन्दी स्कूलों में भेजना फिजूल है। हिन्दी से कहीं ज्यादा अंधकारमय भविष्य उर्दू का है। अच्छा तो यह होता, जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया था कि उर्दू कम से कम तीन राज्यों में बहुत बड़े पैमाने पर बोली जाती है बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तो अच्छा होता कि

उसी समय उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दे दिया जाता। हमारे मन्त्री महोदय का ताल्लुक सोशलिस्ट पार्टी से रहा है और मेरा भी कुछ थोड़ा सा ताल्लुक डा० लोहिया से रहा है। सन 1967 में मुझे याद आता है कि डाक्टर लोहिया ने टिप्पणी की थी कि उर्दू को बिहार और उत्तर प्रदेश में दूसरी राजभाषा का दर्जा मिलना चाहिए और उसके बाद डाक्टर लोहिया की प्रेरणा से ही मैंने यहाँ हिन्दी लेखकों का एक सम्मेलन इस दिल्ली में बुलाया इस बात के समर्थन के लिए कि इन राज्यों में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया जाय। खैर वह लेखकों का सम्मेलन था। उससे क्या होता? लेकिन सरकार तब से लेकर आज तक कतराती रही है और यह तर्क जैसा कि मन्त्री महोदय ने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में कहा कि पर्याप्त संख्या नहीं है, इसलिए उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। मैं उसे उचित नहीं मानता हूँ। क्योंकि सेंसस के जो फिगर हैं वह डिपेंडबुल, प्रमाणिक मुझे नहीं लगते क्योंकि सेंसस के लोग जहाँ पर भी इस तरह के सवाल करते हैं, वह बात मुझे उर्दू वालों ने, मुसलमानों ने खास कर बतायी कि वे हमारी भाषा को हिन्दी लिख लेते हैं क्योंकि उनकी मान्यता है कि उर्दू और हिन्दी एक ही भाषाएँ हैं। बुनियादी तौर पर हो सकता है लेकिन व्यवहारिक तौर पर हिन्दी और उर्दू अलग अलग हैं क्योंकि दोनों की स्क्रिप्ट अलग अलग है और जब तक स्क्रिप्ट अलग अलग रहेगी तब तक भाषा भी अलग अलग रहेगी। सेंसस के आंकड़े या फिगर गलत हैं अगर सेंसस सही भी है तो शासन तर्क से नहीं चलता है तर्क बदला जा सकता है। उर्दू जबान बोलने वालों की भावनाओं को समझते हुए और कितनी असुरक्षा में इन सिक्योरिटी में रह रहे हैं इसको देखते हुए, सरकार को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए और उर्दू को कम से कम इन तीन राज्यों में दूसरी राजभाषा का दर्जा देना चाहिए।



इसके अलावा टेस्टबूकों की बात भी कही गयी इस रिपोर्ट में कि पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ जो कि खुद इन्हीं इलाकों से आये हुए हैं, जैसे एक छोट से शहर को लिया जा सकता है अगर वहाँ कोई अपने बच्चे को उर्दू में स्कूल में शिक्षा देना चाहता है तो पहले तो वहाँ उर्दू की व्यवस्था ही नहीं है। अगर व्यवस्था है भी तो यह दिखा दिया जायगा कि पुस्तकें नहीं हैं, पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं तो ऐसी हालत में हम कैसे उम्मीद करते हैं कि लोग अपने बच्चों को उर्दू के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नतीजा यह हुआ है कि जिनके खानदान में 300 साल से उर्दू बोली जाती थी जब आज उनसे पूछा जाता है कि आपकी मातृभाषा क्या है तो वह कहते हैं कि हिन्दी। क्योंकि वे सोचते हैं कि हिन्दी कहने में ही सुरक्षा है। हो सकता है कि वह दिन भी हमें देखना पड़े कि मुसलमान 10 साल बाद अगर उससे पूछा जाय कि आपका धर्म क्या है तो शायद उसे जवाब देना पड़े कि हिन्दू। ऐसी नीबट न आये कि किसी को डर के मारे या भयवश अपने धर्म या अपनी भाषा को झुलाना पड़े। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कांग्रेस शासन की बात भूल जायें। यह राजनीति का सवाल नहीं है। यह सवाल सामाजिक और ऐतिहासिक है और उसको सुधारे, तथा जो भी उसकी जरूरियात हों उनको पूरा करें। आज अगर उर्दू थोड़ी बहुत कहीं जिन्दा है तो पुलिस थानों में जिन्दा है क्योंकि पुलिस थानों में अब भी रपट या एफ०आई० आर० जिसको कहते हैं वह हिन्दी या उर्दू में ही लिखी जाती है। यह एक अजीब बात है कि उर्दू को जगह भी मिली तो कहां? कोतवाली में और बाजारों में। लेकिन उर्दू को आज प्रशासन में जगह नहीं है, क्योंकि प्रशासन में पहला स्थान अंग्रेजी का है और दूसरा स्थान हिन्दी का। झगड़ा हिन्दी और उर्दू का नहीं है। बल्कि झगड़ा तमाम भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी का है और इस सवाल

को डाक्टर लोहिया ने बड़ी खूबसूरती के साथ देश के सामने रखा था।

दूसरी बात यह है कि हिन्दी के लोग अक्सर यह तर्क देते हैं और इस रिपोर्ट, स्टेटमेंट आफ लैंग्वेज में भी यह स्वीकार किया गया है और कहा गया है कि यह हिन्दी का एक वैरियेशन है। अगर उर्दू जुबान हिन्दी का ही एक प्रकार है तो मैं यह तर्क करना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि हिन्दी के लोग गालिब, मीर, सौद, इकबाल और फिराक को अपने कवि के रूप में नहीं स्वीकार करते, क्यों नहीं इन्हें अपनी परम्परा के रूप में स्वीकार करते, क्यों नहीं स्कूलों और कालेजों में इन कवियों को पढ़ाया जाता है। जब उन्हें पढ़ाने का सवाल आता है तब ये कतरा जाते हैं लेकिन वैसे कहने को तर्क वह देते हैं कि उर्दू हिन्दी का ही एक प्रकार है। उपसभाध्यक्ष महोदय, आदर्श स्थिति तो यह होती कि यह विवाद खत्म होता, एक ही जुबान होती—हिन्दुस्तानी। लेकिन जुबान बनाने से नहीं बनती है। जुबान कोई ऐसी चीज नहीं है कि चार आदमी मिल जायें तो जुबान बन जाये और बिगड़ जाये। जुबान अपने आप बनती बिगड़ती है। तो उर्दू के साथ ही दूसरा सवाल सिंधी का भी जुड़ा हुआ है जिस पर मंत्री महोदय को विचार करना चाहिए। सिंधी भाषा बेधरबार लोगों की भाषा मानी जाती है और उसके विकास के लिए पिछले 30 वर्षों में लगभग कुछ नहीं हुआ। उर्दू के लिए तो फिर भी थोड़ा-बहुत हुआ है। उर्दू के लिए कुछ शोर-मुल होता रहता है। द्वेष है उर्दू के प्रति लोगों के मन में लेकिन फिर भी कुछ हल्ला-मुल्ला करने से या वोट वगैरह लेने के लिए कुछ थोड़ा उर्दू के लिए कर देते हैं। लेकिन सिंधी भाषा के लिए कुछ नहीं हुआ है। मैं उनके लेखकों को जानता हूँ और साहित्यकारों को जानता हूँ कि वे किस हालत में रह रहे हैं। इससे मैं कल्पना कर सकता हूँ उनके बोलने वालों की हालत क्या होगी। उपसभाध्यक्ष महोदय, सिंधी केवल



[श्री श्रीकान्त वर्मा]

व्यापारियों की भाषा नहीं है। कोई भी भाषा केवल व्यापारियों और धनियों की भाषा होकर नहीं बनी रहती है, उसके साथ संस्कृति होती है। उसके साथ संस्कृति जुड़ी होती है। इस युग के भाषा-शास्त्री नाम चाम्सकी ने यह बात बार-बार कही है कि कोई भी भाषा दूसरी भाषा से इन्फ़ीरियर नहीं होती क्योंकि उसमें सारी संभावनाएं होती हैं। सारा सवाल उसके विकास का होता है और यह बात नाम चाम्सकी ने तब कही जब कि कुछ अफ्रीकी भाषाओं के बारे में सवाल उठा और उन्होंने कहा, कुछ लोग यह मानते हैं कि अफ्रीकी लोग अपना साहित्य नहीं रच सकते। तब इसका उत्तर देते हुए चाम्सकी ने कहा कि अफ्रीकी भाषा भी उतनी ही विकसित है जितनी दूसरी भाषाएं हैं। उनमें सारी संभावनाएं हैं। उनमें कई ऐसे सिम्बल्स हैं जो अंग्रेजी में नहीं मिलते। फ़ेन्च में नहीं हैं, जर्मन में नहीं हैं और यह सही है कि उन्हें बहुत से सिम्बल जो लेने पड़े हैं वे अफ्रीकी भाषाओं से लेने पड़े हैं और इसका नाम उन्होंने "नीग्रिट्यू" रखा है। इसलिए किसी भी भाषा को मानने के लिए उसकी सामाजिक परंपरा को समझना चाहिए। मैं विशेष रूप से सिंधी के लिए आग्रह करूंगा कि गृह मंत्रालय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि बेघरवार लोगों की ज़बान केवल एक बेघरवार ज़बान होकर न रह जाए। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Before I call the next speaker, Mr. Shahi, the Minister for Finance wants to make a brief statements—only statement, on discussion on that—on Andhra Pradesh and Tamil Nadu.

#### STATEMENT BY MINISTER

##### Natural Calamity in Tamil Nadu and Andhra Pradesh, and grant of Central Relief

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE

(SHRI SATISH AGARWAL): Sir, as the hon. Members of this House are aware a serious calamity has befallen two of the States of the Union—Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Large-Scale damage to life and property has occurred in many districts of these two States as a result of two severe cyclones. The total extent of the damage will be assessed in due course and it is the Central Government's intention to provide appropriate assistance to the two States. In the meanwhile, as a measure of emergency relief the Central Government has decided to sanction immediately an advance of Rs. 5 crores to Tamil Nadu and Andhra Pradesh.

AN HON. MEMBER: Rs. 5 crores to each?

SHRI SATISH AGARWAL: Yes, Rs. 5 crores to Tamil Nadu and Rs. 5 crores to Andhra Pradesh. I am sure the Members of this House will join me in conveying to our brothers and sisters in Tamil Nadu and Andhra Pradesh our deepest sympathy in their difficult moment.

#### MOTION RE. FIFTEENTH AND SIXTEEN REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES IN INDIA—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA): Mr. Shahi, eight to ten minutes.

श्री नागेश्वर प्रसाद शाही (उत्तर प्रदेश):

उपसभाध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे कुछ साथियों ने उर्दू को अपने मुसलमान भाइयों के साथ जोड़ने की कोशिश की है और यह बड़े दुर्भाग्य की बात